संख्या-31/2026/1055/94-1-2026-312(206)/2025

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 12 मई, 2026**

विषय: जनपद प्रयागराज में उप निबन्धक कार्यालय करछना एवं उप निबन्धक कार्यालय सोरांव के निर्माण के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-1775/भवन-2/शि0का0लख0/2026 दिनांक 29.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद प्रयागराज के उप निबंधक कार्यालय करछना एवं उप निबन्धक कार्यालय सोरांव के निर्माण हेतु विभागीय मानक के अनुरुप भूमि उपलब्ध होने के दृष्टिगत कुल आगणित लागत धनराशि रु० 457.90 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु० 228.95 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में कुल लागत रु० 457.90 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में पचास प्रतिशत धनराशि रु० 228.95 लाख (रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नांकित कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

जनपद का नाम/ कार्यदायी संस्था	स्थल का नाम	निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन का प्रकार	भूमि का स्वामित्व का प्रकार एवं क्षेत्रफल (हे०में)	भूमि की उपलब्धता का विवरण हॉ/नहीं	भवन की मानकीकृत लागत/ आगणन (लाख में)	प्रथम किश्त हेतु निर्गत की जाने वाली रु० लाख में।
2	3	4	5	6	7	8
प्रयागराज/ उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि०।	करछना	कार्यालय उ0नि0 करछना	जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 24-04-2026 द्वारा उप निबन्धक कार्यालय करछना के भवन निर्माण हेतु तहसील करछना के ग्राम-हिंदूपुर के गाटा संख्या-179 रकबा-0.6042हे० में से 0.1000हे० भूमि आवंटित/ विभागीय भूमि उपलब्ध है।	हॉ	228.95	114.475
	सोरांव	कार्यालय उ0नि0 सोरांव	जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 09-04-2026 द्वारा उप निबन्धक कार्यालय सोरांव के भवन निर्माण हेतु तहसील सोरांव के गाटा संख्या-358 में 0.095हे० भूमि आवंटित/ विभागीय भूमि उपलब्ध है।	हॉ	228.95	114.475
				कुल योग	**457.90**	**228.95**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

1. महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025, संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनांक 16.07.2024 व समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

2. निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त प्रक्रिया एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा।

4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद में किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

6. कार्यदायी संस्थाओं को कार्य की गुणवत्ता एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु तय समय-सीमा (धनावंटन के पश्चात यथा संम्भव 06 माह के भीतर) में किसी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा।

7. निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने हेतु महानिरीक्षक निबंधन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

8. निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन में टाईम ओवर रन, कॉस्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

9. कार्यों की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो इसे महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

10. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

11. नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

13. कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हो जाये।

14. प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

15. कार्यदायी संस्था द्वारा सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023 /ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/ दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16. महानिरीक्षक निबन्धन की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी की स्वीकृति के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति व टेंडर जारी किये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेंडर कास्ट) के अनुसार पुनरीक्षित करा लिया जायेगा व परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रु० 228.95 लाख (रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-091 लेखा शीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 800-अन्य व्यय, 03 स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण, 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4. मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
5. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि०।
6. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
8. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
9. उप महानिरीक्षक निबंधन/ उपायुक्त स्टाम्प, प्रयागराज।
10. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, प्रयागराज।
11. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।